

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशन विकास विभाग
प्रेमनगर, देहरादून।

उद्धान एवं रेशन अनुभाग:-2

देहरादून: दिनांक 18 जनवरी 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-10 के आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0701-अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-10 के आय-व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या-29 के आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0701-अधिष्ठान के 01-वेतन, 03-महगाई भत्ता तथा 06-अन्य भत्ता मदों में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित कगशः ₹0-9500 हजार, ₹0-1,000 हजार एवं ₹0-80 हजार अर्थात् सम्पूर्ण प्राविधानित ₹0-10780 हजार (₹0 एक करोड़ सात लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार विस्तारों के किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-515(1)/XXVII(1)/2009, दिनांक-28 जुलाई 2009 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैन्युअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 5- व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

-2/-

- 6- व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 7- योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-119-बागवानी एवं साधियों की फसलें-07-शहतूत की खेती एवं रेशन विकास-0701-अधिष्ठान के उप मानक मदों 01-बेतन, 03-महंगाई भत्ता एवं 08-अन्य भत्ता के नामे खाला जायेगा।

भवदीय,

(विनोद कोनिया)
सचिव।

संख्या- /XVI-2/09/7(23)/09 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान बोर्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, षौड़ी/कुमार्यू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०एस०पाण्डे)
अपा सचिव।